

1. डॉ० नूरजहां  
2. प्रकाश चन्द्र**भारत में सामाजिक सुरक्षा एवं संबंधित विकास योजनाएं**

1. आचार्य – राजनीति विज्ञान, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, 2. शोध अध्येता– राजनीति विज्ञान महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर (राजस्थान), भारत

Received-21.09.2023, Revised-24.09.2023, Accepted-28.09.2023 E-mail: aaryavart2013@gmail.com

**सारांश:** सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक एवं विस्तृत अवधारणा है। सामाजिक सुरक्षा में समाज के साथ-साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक व आर्थिक विकास शामिल किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा में श्रमिकों, किसानों, सामान्य महिलाओं, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, विधवा व परित्यागता महिलाओं, वृद्धजनों, बेरोजगारों, विकलांगों आदि सभी की सभी प्रकार से सुरक्षा व कल्याण को शामिल किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा में मुख्यतः बच्चों की शिक्षा का प्रबंध, बेरोजगारों को रोजगार गारंटी या बेरोजगारी भत्ता, प्राकृतिक विपदा से पीड़ित लोगों को आर्थिक व छाद्य सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था करना, गर्भवती महिला के लिए पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा, देखभाल, पोषक पदार्थों की व्यवस्था करना, गर्भवती महिला कर्मिकों को प्रसूता अवकाश, अस्वस्थ कर्मचारी को सवेतन छुट्टी, दुर्घटना पर मुआवजा राशि, विकलांगता व अपंगता पर सहायता राशि देना, दिव्यांगों हेतु पृथक शैक्षणिक व्यवस्था, वृद्धजनों, विधवा, परित्यागता महिला हेतु पेंशन व्यवस्था, परिवार के मुखिया की मृत्यु पर वित्तीय सहायता देना, मजदूरों को न्यूनतम वेतन व रोजगार गारंटी देना, महामारी में निःशुल्क उपचार व टीकाकरण, नवजात शिशुओं का निःशुल्क टीकाकरण व दवाईयाँ, महिलाओं हेतु निःशुल्क प्रसव सुविधा, महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन की गारंटी देना, परिवार नियोजन संबंधी निःशुल्क सुविधाएँ प्रदान करना, बेरोजगारों व महिलाओं को व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु ऋण देना, किसानों, वृद्धजनों को बीमा उपलब्ध कराना, सामाजिक व आर्थिक रूप से निर्बल व पिछड़े वर्गों, अनु. जाति व अनु. जनजाति के शैक्षणिक उत्थान हेतु छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु उपहार योजनाएँ चलाना, बेघरों के लिए निःशुल्क आवास योजना आदि को शामिल किया जाता है।

**सुंजीवित राख- सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, श्रमिकों, किसानों, सामान्य महिलाओं, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, बेरोजगारों, रोजगार**

इन सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक योजनाओं को लागू किया गया है ताकि देश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर एक सुरक्षित एवं सशक्त जीवन दिया जा सके। ये योजनाएँ निम्न प्रकार हैं-

**केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं-जननी सुरक्षा योजना-** यह योजना केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण द्वारा 2005 में प्रारम्भ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली प्रसूता को सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती है ताकि मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सके साथ ही संस्थागत प्रसव को भी बढ़ावा मिले। इस योजना में शहरी प्रसूता महिला को 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि व ग्रामीण प्रसूता महिला को 1400 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। भारत सरकार ने 1 जून 2011 को एक कार्यक्रम जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया है जिसमें माता व शिशु दोनों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

**प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-** माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'स्वच्छ ईंधन बेहतर' जीवन के नारे के साथ 1 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को धुएँ से रहित रसोई की व्यवस्था उपलब्ध करवाकर धुआरहित ग्रामीण भारत का निर्माण करना है और 2019 तक 5 करोड़ एल.पी.जी. कनेक्शन गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाली गरीब महिलाओं को रियायती दर पर एल.पी.जी. कनेक्शन व सिलेण्डर उपलब्ध कराना है। इस योजना में बीपीएल परिवार की महिलाओं को 1600 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सभी घरों में गैस की सुविधा उपलब्ध कराना है।

**बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना-** यह योजना केवल योजना ना होकर एक जागरूकता अभियान है। इस बेटी बचाओ अभियान को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी द्वारा 22 जनवरी को पानीपत हरियाणा से प्रारम्भ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के प्रति समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण को समाप्त कर लोगों को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक करना, बेटियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने व बालिका कल्याण की सभी योजनाओं को लागू कर बेटियों को वास्तव में लाभान्वित करना है अर्थात् बेटियों के लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, शिक्षा को सुनिश्चित कराना व समाज में भागीदारी बढ़ाना आदि शामिल हैं। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा झुझनु जिले से प्रारम्भ की गई। राजस्थान में यह योजना 10 जिलों में बालिकाओं के प्रति भेद-भाव को समाप्त करने, बालिकाओं को सशक्त बनाने तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के माध्यम से बालिकाओं को समाज में एक सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया गया है। यह योजना भी सामाजिक विकास और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से एक अहम भूमिका निभा रही है।

**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (महानरेगा)-** राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को दिनांक 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। बाद में इसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नाम दिया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर कुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो ऐसे वयस्कों को काम के लिए आवेदन करने के 15 दिन के अन्दर काम पाने का हक होगा। अगर 15 दिन की अवधि में काम



उपलब्ध नहीं कराया गया तो मजदूर बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को यथासंभव घर के समीप या 5 किमी के दायरे में रोजगार दिया जाएगा। इस योजना में प्रत्येक परिवार को एक साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी का हक है। इस योजना में यदि कार्य के दौरान मजदूर को चोट लग जाए तो वह मुत इलाज का हकदार हो जाता है। अगर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होगा तो उसे निःशुल्क इलाज के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी का आधा दैनिक भत्ते के रूप में मिलेगा। यदि कार्य के दौरान मजदूर की दुर्घटनावांश मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी तथा मजदूर स्वयं स्थाई रूप से विकलांग हो जाए तो उसे स्वयं केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अनुग्रह राशि पाने का हक है। इस योजना के अन्तर्गत कार्यस्थल पर शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल, विश्राम स्थल तथा प्राथमिक उपचार बॉक्स की व्यवस्था भी की जाती है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलता है जो परिवार स्थाई निवासी होते हैं। परिवार का प्रत्येक वयस्क इस अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी पा सकता है। इस योजना में मजदूरी की दर केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। महिला और पुरुषों को समान दर से मजदूरी दी जाती है।

**स्टैण्ड अप इण्डिया योजना-** स्टैण्ड अप इण्डिया योजना 18 वर्ष से अधिक उम्र के अनु. जाति, अनु. जनजाति व महिला वर्ग को लाभान्वित करने हेतु प्रारम्भ की गई है। इस योजना में केवल ग्रीनफिल्ड परियोजना के अन्तर्गत की सहायता दी जाती है। यह योजना 5 अप्रैल 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत अनु. जाति, जनजाति व महिला अभ्यर्थियों का अपना उद्यम प्रारम्भ करने हेतु 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का व्यवसायिक ऋण दिया जाता है।

**प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना-** यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा 1 फरवरी 2019 को किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रारम्भ की गई थी। इस योजना में भू-धारक कृषकों के परिवार को कृषि, कृषि संबंधी गतिविधियों, घरेलू आवश्यकताओं आदि को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक भू-धारक किसान के परिवार को चार महीने में 2000 रुपये की तीन किश्तें अर्थात् कुल 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी।

**आयुष्मान भारत योजना-** आयुष्मान भारत योजना का केन्द्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय के जन्मोत्सव पर 25 सितम्बर 2018 को शुभारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग को स्वास्थ्य सुविधा व 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। यह योजना लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों को लाभान्वित करने हेतु चलाई गई है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मकान, महिला मुखिया वाला परिवार, अवयस्क परिवार, परिवार में दिव्यांग हो, अनु. जाति या अनु. जनजाति का हो, मजदूर, श्रमिक या भूमिहीन व्यक्ति हो, बेघर व निराश्रित, मिखारी, आदिवासी, कानून रूप से मुक्त बंधुआ आदि को शामिल किया गया है। इसके साथ शहरी क्षेत्र के मिखारी, कूड़ा उठाने वाले, सब्जीवाले, चर्मकार, घरेलू व्यवसायिक, फेरी वाले, सड़क किनारे छोटी दुकान वाले, मकान निर्माण में सहायक मजदूर, पानी-बिजली मिस्त्री, सुरक्षा गार्ड, कुली, भार उठाने वाले, सफाई कर्मी, हस्तकला वाले, ड्राईवर, दर्जी, रिक्शा चालक, दुकान पर कार्यरत कर्मी आदि इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। 28 फरवरी 2018 तक के राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड धारक ही आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा जैसे अस्पताल में भर्ती होना, रजिस्ट्रेशन, दवाईयां, चिकित्सक परामर्श शुल्क आदि सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।

**स्वावलम्बन योजना-** इस योजना को ग्रामीण महिलाओं, विधवा, परित्यागता, व गरीब महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में शुरू किया गया। इस योजना में महिलाओं को आर.एस.एल.डी.सी. और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पारम्परिक व गैर पारम्परिक व्यवसायों जैसे- रेडीमेड गारमेन्ट्स, ब्यूटीशियन, सॉट टायज, कपड़े के बैग व अन्य आइटम बनाना, हैण्डमेड पेपर, लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं, पेंटिंग, मुर्तिकला, सिलाई आदि में आय जनक प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हें स्वरोजगार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य जनकल्याणकारी योजनाओं से युवाओं को लाभान्वित करना एवं नवीन कार्य करने के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करना है जिससे देश का युवा वर्ग नए-नए कार्यों को उत्कृष्टता से कर नए कीर्तिमान स्थापित कर सके।

**प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना-** यह योजना बेटियों के लिए भविष्य में धन जमा करने के लिए यह योजना चलाई गई इस योजना में पी.पी.एफ. कि अपेक्षा ज्यादा ब्याज मिलता है। यह माता-पिता की टैक्स प्लानिंग में भी सहायक है। वर्तमान में 7.6 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। इस योजना के तहत 10 साल से छोटी बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। यह खाता तभी खुलवा सकते जब आप प्राकृतिक या कानूनी रूप से माता-पिता हो। एक बेटे के नाम एक ही खाता खुलवा सकते हैं। मगर जुड़वा होने पर तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं। 18 साल पूर्ण होने पर ही इस खातों से रुपये निकाल सकते हैं।

**प्रधानमंत्री जन-धन योजना-** यह योजना कमजोर वर्गों, कम आय और वंचित वर्गों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती है जैसे मूल बचत, बीमा तथा पेंशन उपलब्धता सुनिश्चित करना है। विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ इसी खाते पर संभव है। इस योजना में एक लाख रुपये का बीमा कवर और जमा राशि पर ब्याज, 30,000 रु का बीमा उसकी मृत्युपरान्त सामान्य शर्तों पर देय होगा। परिवार की स्त्रियों के लिए 5,000/- रुपये तक ओवर ड्राट की सुविधा उपलब्ध है।

**दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-** यह योजना 25 सितम्बर 2014 को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस योजना में 15 से 35 वर्ष की आयु के गरीब ग्रामीण युवकों को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का प्रयास किया गया है। यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने का एक मिशन है। इस योजना में ऐसे गरीब ग्रामीण युवाओं को स्थायी रोजगार दिया जाता है। जो कुशल होने के लिए तैयार हैं। इस योजना ने गांव के गरीब युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाकर एवं उन्हें



जागरूक बनाकर उन्हें एक नई पहचान प्रदान की है।

**राज्य सरकार (राजस्थान सरकार) द्वारा संचालित योजनाएं— मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना—** भारत देश व राजस्थान राज्य की सबसे ज्यादा लाभार्थियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को गई। सरकारी चिकित्सालयों में रोगी को मुक्त दवा का लाभ दिया गया। इस योजना में 1594 प्रकार की दवाइयां, 928 सर्जिकल एवं 185 सूचर्स सहित 2707 दवाइयां, सर्जिकल व सूचर्स उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में दवा वितरण हेतु 33 जिला मुख्यालयों पर 40 औषधि भण्डार गृह स्थापित हैं। इस योजना में आपातकालीन व इण्डोर दो प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। जो 24 घण्टे उपलब्ध रहती हैं। यह योजना राजस्थान के सभी नागरिकों को मुक्त दवा के द्वारा सामाजिक सुरक्षा में सहायता प्रदान करती है।

**मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना—** यह योजना 7 अप्रैल 2013 से प्रारम्भ की गई। नागरिकों को सम्पूर्ण उपचार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु यह योजना लागू की गई जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराकर मानव जाति का कल्याण करना है। यह योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू की गई।

**एक रुपये किलो गेहूँ—** यह योजना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई गई है राष्ट्र खाद्य सुरक्षा योजना के द्वारा अत्योदय राशन कार्ड धारकों को 35 किलो ग्राम गेहूँ तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल राशन कार्ड धारकों को 5 किलो ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह एक रुपये किलो की दर से गेहूँ दिया जाता है।

**पालनहार योजना—** यह योजना सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की गई है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जा सकती बल्कि बच्चों के निकटतम रिश्तेदार/ परिचित व्यक्ति/ वयस्क, भाई/ बहन को पालनहार बनाकर उसकी देखभाल, पालन पोषण हेतु अर्थात् आर्थिक रूप से सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत अनाथ बच्चों, पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चों, एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चों, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चों, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदण्ड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चों, विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चों, पेंशन प्राप्त कर रही परित्याक्ता/ तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों, सिलिकोसिस पीड़ित माता-पिता के बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है। पालनहार परिवार को वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार तक होनी चाहिए। बच्चों की आयु 18 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष तक राजस्थान में निवास कर रहे हो। जुलाई 2023 से राशि में वृद्धि की गई है। 0-6 वर्ष तक बच्चों को प्रतिमाह 500 रुपये सहायता राशि को बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिमाह तथा 6-18 वर्ष आयु के बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई। विधवा व नाता श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी के बच्चों को 2000 रुपये वार्षिक एक किस्त सहायता प्रदान की जाएगी। वर्तमान में 2474 करोड़ रुपये का कर 6 लाख 87 हजार लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। "पालनहार का दायित्व - पालनहार को ऐसे बच्चों को अपने घर में रखना होगा एवं पालनहार द्वारा ऐसे बच्चों को घर में परिवार जैसी सामान्य सुविधाएं देनी होंगी। पालनहार द्वारा बच्चे के प्रति अपने बच्चों के समान व्यवहार, स्नेह एवं देख रेख करनी होगी। किसी भी स्थिति में बच्चे को अमानवीय/अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने देंगे। पालनहार द्वारा बच्चों की देखरेख, शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाएगा।"

**भामाशाह योजना—** भामाशाह योजना राजस्थान की मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा अगस्त महीने में वर्ष 2014 में प्रारम्भ की गई। महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से जुड़ी इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा भी देना है। इस योजना में परिवार की महिला मुखिया के नाम से कार्ड जारी कर कार्ड को बैंक खाता से जोड़ा जाता है किन्तु महिला मुखिया का 21 वर्ष से अधिक उम्र की होना आवश्यक है। इस कार्ड के आधार पर लगभग 54 सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को नगद व गैर नगद रूप में मिलेगा। इस योजना का लाभ दिलाने हेतु राजस्थान में 35 हजार से भी अधिक भामाशाह कार्ड केन्द्र शुरू किये गए थे। 18 दिसम्बर 2019 को भामाशाह कार्ड योजना का नाम परिवर्तित कर नया नाम जनाधार कार्ड योजना रखा गया। इस कार्ड में 10 अंकीय पहचान संख्या अंकित होगी। महिला सशक्तीकरण से जुड़ी इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करके उनको विकास की दिशा में ले जाया जाएगा।

**मुख्यमंत्री राजश्री योजना—** बालिकाओं के सर्वांगीण विकास, बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक एवं सम्माननीय दृष्टिकोण उत्पन्न करने व उनके स्वास्थ्य एवं शैक्षिक स्थिति में सुधार हेतु 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा किया गया। इस योजना की लाभार्थी राजकीय तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता होती है। इस योजना के अन्तर्गत कुल 6 किशतों में प्रत्येक लाभार्थी को 50,000 रुपये की धनराशि देने का प्रावधान है। यह योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर लागू की गई है। यह बेटियों के उत्थान की एक अनूठी योजना है।

**राजस्थान आई.एम. शक्ति उद्धान योजना—** मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 19 नवम्बर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। यह योजना राज्य सरकार द्वारा राज्य की सभी महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत बालिकाओं और महिलाओं को फ्री में सेनेटरी पेड दिए जायेंगे। जिनका वितरण विद्यालयों, महाविद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर उन्हें रोग मुक्त बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना है। इस योजना की जानकारी देने की जिम्मेदारी सरकार ने राजस्थान की महिला स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संस्थानों को दी है जो समय-समय पर इस योजना से संबंधी जागरूकता केम्पेन चलायेंगे ताकि बालिकाओं और महिलाओं को इस योजना की



जानकारी प्राप्त हो सके। इस योजना के अर्न्तगत फ्री सेनेटरी नेपकीन हेतु राज्य सरकार द्वारा लगभग 200 करोड़ का बजट तय किया गया है। राजस्थान में मूल रूप से रह रही महिलाएं अथवा छात्राएं इस योजना की पात्र होंगी। इस योजना में मुख्य रूप से गावों में रहने वाली महिलाओं और बालिकाओं को जो आर्थिक रूप से दुर्बल हैं जो शर्म के कारण या पैसे की कमी के कारण या अन्य कारणों से सेनेटरी नेपकीन नहीं खरीद सकती उन्हें सेनेटरी नेपकीन निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।

**इंदिरा रसोई योजना-** इस योजना का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य के सभी नगरीय निकायों में दिनांक 20.08.2020 को किया गया। इस योजना को लागू करने के पीछे राज्य सरकार का एक ही संकल्प है कि राज्य का कोई व्यक्ति भूखा ना सोये। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर या जरूरतमंद लोगों को दो समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर पर दिया जाता है। इस योजना के अर्न्तगत लाभार्थी को 8 रुपये प्रति थाली दोपहर का भोजन और 8 रुपये प्रति थाली रात्रि का भोजन दिया जाता है। इन्दिरा रसोई योजना एक सेवा भाव से जुड़ी योजना है जिसका एक ही उद्देश्य है राज्य का कोई व्यक्ति भूखा ना रहे उसे दो वक्त की रोटी उपलब्ध हो सके।

**इंदिरा गांधी फ्री स्मार्ट फोन योजना-** इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अगस्त 2023 को राजस्थान के निवासियों के लिए की गई। इस योजना में राज्य की महिलाओं को फ्री में स्मार्ट फोन वितरित किए गये। साथ ही 3 साल का फ्री इन्टरनेट रिचार्ज भी दिया जाएगा। यह फ्री स्मार्ट फोन परिवार की महिला मुखिया को मिलेगा। इस फ्री मोबाइल को प्राप्त करने के लिए लिस्ट में नाम होना भी आवश्यक है। जिन महिलाओं का जनआधार चिरंजीवी योजना से जुड़ा हुआ है उसी परिवार की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

महिला मुखिया के अतिरिक्त राज्य में डीग्री या डिप्लोमा करने वाली या कक्षा 9 से 12वी तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी फ्री स्मार्ट फोन वितरित किया जाएगा। इसके अलावा नरेगा में 100 दिन पूर्ण करने वाली और शहरी रोजगार में 50 दिन पूरे करने वाली या पेंशनर या विधवा पेंशनर को भी फ्री स्मार्ट फोन वितरित किया जाएगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों, शहरों, कस्बों आदि में फ्री मोबाइल वितरण कैम्प लगाये जा रहे हैं। इस योजना में महिलाओं को अपनी पसंद का मोबाइल चुनने का अधिकार है। इस योजना के द्वारा महिलाओं को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़कर और उन्नत और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है साथ ही महिलाओं का विकास कर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है जिससे राजस्थान की महिलाओं में खुशी की लहर आ गयी।

**मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 2023-** यह योजना गहलोत सरकार द्वारा अगस्त 2023 में राज्य के 1 करोड़ 6 लाख गरीब परिवारों को हर माह निःशुल्क खाद्य-सामग्री एक पैकेट के रूप में वितरित किये जायेगे। जिसमें 1 किलो दाल, चना, नमक, 100 ग्राम धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर, 1 लीटर तेल होगा।

इस प्रत्येक पैकेट की कीमत 370 रुपये होगी। यह योजना राजस्थान में कोई भूखा ना सोये के उद्देश्य से व मंहगाई से राहत पाने के लिए शुरू की गई। इस योजना का लाभ राजस्थान के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल सभी परिवार या जिन परिवारों को महामारी के दौरान 5500 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा मिली है उनको मिलेगा। लाभार्थी राजस्थान का स्थायी नागरिक है वह इस योजना का लाभ ले सकता है।

लाभार्थियों को सहायता व रजिस्ट्रेशन हेतु हर गांव, शहर, कस्बों आदि जगह-जगह पर मंहगाई राहत कैम्प शुरू किए गये जिनमें रजिस्ट्रेशन के द्वारा कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा जैसे - चिरंजीवी कार्ड दवा व बीमा, फ्री बिजली योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट आदि। इन योजनाओं का उपयोग कर विकासशील देश अपने देश की विकास की गति को तेज करते हैं। भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई इन योजनाओं के द्वारा जरूरतमंदों व असहाय लोगों के विकास का प्रयास किया गया है।

अतः प्रस्तुत शोध पत्र में सामाजिक सुरक्षा संचालित योजनाओं (भारत एवं राज्य सरकार) का प्रस्तुतीकरण किया गया है। मुख्यतः इस शोध पत्र में 2005 से 2023 तक की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत करके भारत देश के सामाजिक विकास को निरन्तर सतत् संचालित रखने में सरकारी प्रयासों को प्रस्तुत करके देश के विकास की गति से अवगत कराने का प्रयास किया गया तथा इस विषय से सम्बन्धित शोध कार्यों को दिशा देने का प्रयास भी किया गया है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, विकास कुमार, : योजनाएं - राजस्थान व भारत सरकार की प्रमुख धाणेराव गौरव सिंह योजनाएं, च्यवन प्रकाशन, जयपुर, 2023.
2. कोटड़ा, मनोहर सिंह, : राजस्थान सरकार की नवीनतम लैंगशिप एवं अन्य रत्नु दीपा योजनाएं/कार्यक्रम, संजीव प्रकाशन, नई दिल्ली, 2022
3. आर्य, राकेश कुमार : भारतीय राष्ट्र की समस्यायें और उनके समाधान, संजीव प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011.
4. बनर्जी, डॉ. अनिन्दिता : बाल विकास, ग्रामीण पुस्तक भवन, प्रतापगढ़, उत्तरप्रदेश, 2010.
5. बसु, आचार्य, डॉ. दुर्गादास : भारत का संविधान-एक परिचय, वाधवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली 2006.
6. चौधरी, ओम प्रकाश: योजनाएं प्लस नीतिया, अवनी पब्लिकेशन राजस्थान, 2022.
7. बाबेल, डॉ. बन्तीलाल : पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास योजनाएं (राजस्थान के विशेष संदर्भ में), राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी



जयपुर, 2019

**सामाचार पत्र-पत्रिकाएं -**

योजना मासिक पत्रिका

दैनिक भास्कर

प्रतियोगिता दर्पण

सुजस राजस्थान

वेबसाइटस -

<http://www.rlsa.gov.in>

<http://www.wikipidia.com>

<http://www.scotbuzz.org>

<http://rsby.gov.in>

<http://google.com>

<http://www.dsg.gov.za>

\*\*\*\*\*